



जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर अपने रुख में लचीलापन लाते हुए भाजपा ने कहा है कि इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए कि इस संवैधानिक प्रावधान से राज्य के कोई फायदा हुआ है या नहीं। पार्टी ने संकेत दिया है कि अगर इस तरह के विचार उभर कर आते तो वह इसे रद्द करने की मांग के छोड़ सकते हैं।

भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना जाने के बाद राज्य में अपनी पहली रैली में नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रही है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के विचारों का समर्थन किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 लाभदायक साबित हुआ तब उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। मोदी ने कहा, 'संवैधानिक मुताबिक इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो या जारी रहे। कम से कम इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के फायदा हुआ है या नहीं।' यह भाजपा के उस रुख के खिलाफ है, जिसमें वह भारत में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद के पूरी तरह रद्द करने की मांग करती रही है।

मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समय के साथ अनुच्छेद 370 समाप्त होगा। उन्होंने कहा, 'क्या कांग्रेस नेहरू के बयान के साथ होगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ?' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिकता के लिए अनुच्छेद 370 के ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। संवैधानिक विशेषज्ञों के इस पर चर्चा करनी चाहिए।

इस प्रावधान का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के समान अधिकार नहीं दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के परिवार का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, 'अगर उमर ने कश्मीर से बाहर विवाह किया, तो उनका नागरिक के रूप में अधिकार बना हुआ है। जबकि उनकी बहन सारा का अधिकार इसी वजह से समाप्त हो जाता है। क्या यह राज्य में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है?'

चीन से संबंधित नीति पर केंद्र पर नशाना साधते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चीन की ओर से भारत से लगी सीमा पर ग्रामीणों के सीमा कर्ड बांटा गया है। उन्होंने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा दूरसंचार मंत्रालय इसे उपलब्ध नहीं कर सकता?' मोदी ने संवैधानिक 73वें संशोधन का भी उल्लेख किया जिसके तहत पंचायतों के वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं।

राज्य में सरकार चला रही नेशनल कंग्रेस पर नशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'जो लोग स्वायत्तता की बात करते हैं, वे ही अपने निर्वाचित स्थानीय निकायों के इसे प्रदान करने के तैयार नहीं हैं। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लपित रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून जम्मू-कश्मीर के छोड़ कर अन्य सभी जगहों पर लागू है। मोदी ने कहा कि 60 साल से वे पृथक् राज्य (स्वायत्तता) की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के क्या मिला? उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मिला और कोई जवाबदेही नहीं है। अलग राज्य के नाम पर अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी ने कहा, 'अच्छा यह होता कि वे बेहतर राज्य बनाने पर ध्यान देते।'

राज्य सरकार के आंकड़ों में प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आने की बात कही गई है हालांकि मोदी ने दावा किया कि राज्य में पर्यटन प्रभावित हुआ

है। मोदी ने कहा, 'यहां पर्यटन प्रभावित हो रहा है। पर्यटक हमिचल प्रदेश जा रहे हैं। सौंदर्य और श्रद्धा के लिए अच्छा पर्यटन स्थल है, यहां पर 'हृदी सनिमा के 100 साल पूरा होने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, 'यहां काफी फिल्मों की शूटिंग होती है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं फिल्म संस्थान स्थापित किया गया? यह दुखद है कि उनकी रुचि विकास में नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ा देने के लिए सरकार लेह के रास्ते कैलाश मानसरोवर के मार्ग पर क्यों नहीं विचार करती है? राज्य में कई केंद्रीय कानून को लागू करने में कांग्रेस के विपक्ष रहने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, 'राज्य में भेजा जाने वाला पैसा लूटा जा रहा है। इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। अलगाववाद को बढ़ा दिया जा रहा है।'

इससे पहले रैली में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी चीन के साथ सीमा समझौता के विषय को संसद में उठाएगी। उन्होंने कहा, 'हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन गए थे। वहां उन्होंने चीन के साथ सीमा सहयोग समझौता किया था। इसमें कई विवादास्पद उपबंध हैं।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने समझौता करने से पहले संसद के विश्वास में लेना जरूरी नहीं समझा।

(भाषा)